THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). No agreement has been signed with Libya this year. However, a meeting of the Indo-Libyan Joint Commission was held in Tripoli from February 25 to March 2. The Indian delegation was led by Dr. Charanjit Chanana, Minister of State for Industry. A number of projects were identified for further cooperation between India and Libya.

जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से पठानकोट—काण्डला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 को चौड़ा करना

6091. श्री बद्रि चन्द्र जैन : क्या **नौवहन** और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से हो कर पठानकोट काण्डला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के मानदण्ड के अनुरूप नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए निर्धारित किए गए मानक के अनुसार उपरोक्त सड़क को चौड़ा करने का कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे चौड़ा करने का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15 जो पठानकोट से काण्डला तक है, पंजाब (367 कि० मी०) राजस्थान (860 कि० मी०) और गुजरात (272 कि० मी०) से हो कर गुजरता है । इस राज मार्ग की चौड़ाई, यातायात की आवश्यकता अनुसार मुख्यतः इकहरी लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरूप है । सड़क की चौड़ाई बहुत से ऐसे स्थानों पर कुछ कम ही है, जो रेतीले क्षेत्र में पड़ते हैं । रेतीली भूमि होने के कारण यह क्षेत्रीय समस्या है । वहां प्राकृतिक परिस्थितियां असाधारण होने के कारण सड़क की पटरी/पुश्ते टूट जाते हैं । परन्तु, मौजूदा सड़क को, मध्यम दर्जे की दो लेनों की सड़क में चौड़ा करने (5.5 मी० चौड़ाई) और सड़क की पटरी के बचाव के लिए पहले से ही कदम उठाए गए हैं और बीकानेर-गंगानगर खंड में लगभग 90 कि० मी० और बीकानेर-बापखंड में लगभग 58 कि० मी० सड़क के लिए अनुमान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं । चूंकि, राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करना/ सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए भारत सरकार इस समस्या पर पूरी तरह नजर रखे हुए है । । राजस्थान में सूरतगढ़ से पंजाब तक लगभग 400 कि० मी० लम्बी सड़क को, और कुछ भाग जो पंजाब और गुजरात में पड़ता है, उसे दो लेनों तक चौड़ा करने पर 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जाएगा । यातायात आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और धन उपलब्ध होने जैसी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

ट्रेन कण्ट्रोलर

6092. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेन कण्ट्रोलरों की प्रायः किस पद पर पदोन्नति की जाती है; और

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा उनकी पदोन्नतियों तथा उनके दर्जे में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवतः आशय सेक्शन कण्ट्रोलरों के पदों से है । यदि हां, तो 470–750 रु० (सं० वे०) के सेक्शन कण्ट्रोलर 700–900 रु० (स० वे०) के वेतन के उप मुख्य कण्ट्रोलरों और 840–1040 रु० के वेतनमान के मुख्य कण्ट्रोलरों तथा इससे आगे वर्ग "ख" (श्रेणी–2) की कोटियों में पदोन्नति के पात्र हैं ।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, कर्मचारियों की इस कोटि के लिए पदोन्नति के पर्याप्त सारणियां पहले से ही हैं ।

Modernisation of Ports

6093. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) Whether Government are considering a proposal to modernise major ports in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). Modernisation and improvement of Port facilities is a continuous process. In the 6th Five Year Plan for 1980—85, emphasis has been laid on modernisation of the existing port facilities and providing additional capacities to meet the expanding needs of the country. A sum of Rs. 531 crores has been allocated for the 10 major ports in the 1980—85 plan for this purpose. Some of the important schemes aiming at modernisation and development of major ports are:

(i) Installation of container handling facilities at Bombay, Cochin and Madras.

(ii) Acquisition of cargo handling equipment by the ports.

(iii) Construction of new berths with modern facilities at Kandle, Mormugao, Mangalore, Nhava-Sheva (Bombay), Paradip, Tuticorin and Visakhapatnam.

Pooling of Natural Resources of Non-Aligned Countries

6094. SHRI HARINATH MISRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have emphasised the need for pooling of natural resources of non-aligned countries in their recent deliberations at New Delhi in February, 1981;

(b) if so, the consensus arrived at and the names of the countries that have agreed with the suggestion; and

(c) the steps that have been taken or are proposed to be taken in the light of the consensus?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) to (c). There was no specific discussion on the question of pooling of natural resources for non-aligned countries in the meeting of their Foreign Ministers held in New Delhi in February, 1981. However, the Ministers reiterated the "importance of exploring, defining and exploiting the immediate possibilities of mutual cooperation among the non-aligned and other developing countries in all fields in order to ensure a more rational use of available resources of all kinds for their individual and mutual benefit and their collective economic progress."